बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 163

पहला कदम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कई ऐसे प्रशासनिक और कर संबंधी बदलावों की घोषणा की जिनका लक्ष्य देश की ठिठकी हुई अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकना है। मंदी को देखते हुए सरकार की ओर से ऐसे कुछ कदमों की अत्यंत आवश्यकता थी। बहरहाल, फिलहाल ऐसी राजकोषीय गुंजाइश नहीं है जिसके तहत किसी तरह का आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। यह राहत की बात है कि सरकार अतिरिक्त व्यय को लेकर सचेत है और सीमित राजकोषीय प्रभाव वाले उपायों पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है। यह बात भी काबिले तारीफ है कि सरकार सुनने को तैयार है और वह मान रही है कि देश की अर्थव्यवस्था में दिक्कतें हैं।

सरकार ने जिन उपायों की घोषणा की है उनमें क्षेत्र आधारित घोषणाएं भी हैं और सामान्य उपाय भी। इन घोषणाओं में शायद सबसे अहम घोषणा वह थी जिसमें कहा गया कि पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) का लंबित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बकाया 30 दिन की तय अवधि में निपटाया जाएगा। इतना ही नहीं भविष्य में तमाम नए बकाये को 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। आशा है कि ऐसा करने से रोजगार उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में कार्यशील पूंजी की कमी कुछ हद तक दूर होगी। सरकार को वित्तीय तंत्र को और सुगम बनाना होगा। फिलहाल यह तंत्र सरकारी बैंकों के तनाव और आईएलऐंडएफएस संकट के परेशानी में नजर आ रहा है। बैंकरों को अतिउत्साही जांच आदि से कुछ बचाव उपलब्ध कराया गया है और सरकारी बैंकों में नई पूंजी डाली जा रही है। इसकी व्यवस्था बजट में ही की जा चुकी थी और सरकार का मानना है कि इससे बैंकों को वृद्धि के लिए कुछ पूंजी मिलेगी। बीते कई दशकों के सबसे बुरे वर्ष का सामना कर रहे वाहन क्षेत्र को भी कुछ राहत दी जा रही है, हालांकि यह राहत उद्योग की इच्छा के मुताबिक कर कटौती के रूप में नहीं दी जा रही है। इसकी जगह सरकार ने उच्च पंजीयन शुल्क को फिलहाल टाल दिया है और इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही कुछ नियामकीय अनिश्चितता को दूर किया है।

कुछ हालिया निर्णयों को पूरी तरह या आंशिक तौर पर वापस लिया गया है। उदाहरण के लिए मंत्री ने दोहराया कि वित्त मंत्रालय कानून की उस धारा को अधिसूचित नहीं करने जा रहा है जिसके तहत कारोबारी सामाजिक उत्तरदायित्व के नियमों के उल्लंघन को आपराधिक करार दिया जाता। पहली बात तो यह कि इसे कभी पारित ही नहीं होना चाहिए था। आयकर अधिभार में किए गए जिस इजाफे ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के एक धड़े को प्रभावित किया था और बाजार में एक किस्म की अफरातफरी पैदा की थी उसे भी आंशिक तौर पर बदला गया है। सरकार को इसे पूरी तरह वापस ले लेना था क्योंकि यह कर ढांचे में जटिलताएं पैदा करेगा। कुल मिलाकर इनमें से कई प्रावधान सुखद हैं। खासतौर पर वित्त मंत्री द्वारा संपत्ति निर्माण करने वालों के संरक्षण और कर मांग में पारदर्शिता बढ़ाने जैसी बातें।

ये उपाय दर्शाते हैं कि सरकार अब संकट को नकारने के दौर से बाहर आ चुकी है और यह मान रही है कि देश की अर्थव्यवस्था गंभीर समस्याओं से दो चार है। इतना ही नहीं वह बिना राजकोषीय संतुलन को छेड़े चक्रीय समस्याओं को हल भी करना चाहती है।

जहां तक बात है गहन ढांचागत दिक्कतों की तो उन्हें हल करना शेष है और निवेश भी बढ़ाना है। इसके लिए केंद्र सरकार को काफी काम करना होगा। उसे राज्यों के साथ मिलकर उत्पादन कारक बाजार के लंबित सुधारों को अंजाम देना होगा। सरकार ने आर्थिक मंदी दूर करने की प्रतिबद्धता दिखाई है अब उसे ढांचागत सुधारों की ओर बढ़ना चाहिए।

अजय मोहंती

पशु उत्पाद निर्यात बढ़ाने के और प्रयास की दरकार

पालतू पशुओं की गणना से सामने आए आरंभिक आंकड़े बताते हैं कि न केवल उनकी उत्पादकता में सुधार हो रहा है बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में उनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है। बता रहे हैं **नीलकंठ मिश्रा**

सरकार हर पांच वर्ष के आसपास पालतू पशुओं की गणना करती है। ऐसी 20वीं गणना गत वर्ष की गई। इससे पिछली गणना 2012 में जबकि पहली पशुगणना 1919 में की गई थी। ताजा पशुगणना के कुछ आरंभिक आंकड़े आ चुके हैं।

ये आंकड़े देश की कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर हमारी समझ बढ़ाने की दृष्टि से पर्याप्त हैं। देश के कुल कृषि उत्पादन में पालतू पशुओं का योगदान एक तिहाई से अधिक है। इतना ही नहीं वर्ष 2012 से 2016 के बीच हुई चरणबद्ध वृद्धि में इसका योगदान करीब आधा रहा।

इन दोनों पशुगणना के बीच केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने उत्पादन में वृद्धि के जो आंकड़े पेश किए, उसकी तुलना में विभिन्न श्रेणियों में पशुओं की तादाद बहुत कम बढ़ी। उदाहरण के लिए इस अवधि में दुधारू पशुओं की तादाद में बदलाव नहीं आया लेकिन दूध के उत्पादन की दर सालाना पांच फीसदी से अधिक बढ़ी। इसी प्रकार मांस के उत्पादन में सालाना चार फीसदी की बढ़ोतरी आई जबकि बकरियों और भेड़ों की तादाद केवल एक फीसदी वार्षिक की दर से बढ़ी। सुअर की आबादी जहां 2012 के स्तर से 20 फीसदी गिरी वहीं पोर्क का वार्षिक उत्पादन इससे तेज गति से बढ़ा।

जीडीपी के आंकड़ों की सच्चाई से जुड़ी हालिया बहस को देखते हुए कई लोग कह सकते हैं कि इस मामले में सीएसओ का आकलन गलत है। परंतु इस विसंगति का कहीं अधिक ठोस स्पष्टीकरण मौजूद है। मसलन दूध की बात करें तो गायों और भैंसों की तादाद सन 1997 से लगभग अपरिवर्तित है लेकिन बैल और भैंसे की संख्या कम हो रही है जबकि गाय-भैंस की संख्या बढ़ रही है। 2017 की गणना में बैल और भैंसे की तादाद 31 फीसदी गिरकर 4.7 करोड़ रह गई जबकि गाय-भैंस 18 फीसदी बढ़कर 14.5 करोड़ हो गईं। दुधारू गाय और भैंस की संख्या भी 2012 की तुलना में 5 फीसदी बढ़ी। ज्यादा दूध देने वाली संकर नस्ल के दुधारू पशुओं की तादाद 30 फीसदी बढ़ने से औसत उत्पादन में भी काफी सुधार हुआ। यानी दूध उत्पादन में 33 फीसदी बढ़ोतरी को इससे समझा जा सकता है।

पशुपालन में मानव के प्रयास पशुओं की तादाद के अनुरूप ही रहते हैं। इसका मतलब प्रति व्यक्ति आधार पर क्षमता और आय में सुधार हुआ। कीमतों में बढ़ोतरी धीमी होने के बावजूद दूध की आपूर्ति सुधरने की बात भी इससे समझी जा सकती है। बैल और भैंसे की तादाद में कमी आने का भी लाभ है। पहले जो चारा 2.1 करोड़ बैल और भैंस खाते थे वही अब उनकी जगह लेने वाले 2.2 करोड़ दुधारू जानवर खाते हैं।

उत्पादन लागत में कमी से जुड़ा एक अन्य दिलचस्प तथ्य है। 19वीं और 20वीं पशुगणना के बीच एक ओर जहां देश में पालतू पशुओं की तादाद केवल 4 फीसदी बढ़ी वहीं झारखंड राज्य में यह 31 फीसदी और ओडिशा, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में 24 से 26 फीसदी की दर से बढ़ी। अन्य राज्यों में इन पशुओं की तादाद तीन फीसदी तक कम हुई। तेलंगाना में इनकी तादाद शायद इसलिए बढ़ी क्योंकि राज्य सरकार ने योजना के तहत 84 लाख भेड़ें चरवाहा परिवारों को दीं। परंतु बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हुई वृद्धि के लिए संभवत: दूरदराज इलाकों तक बुनियादी सुविधाओं में सुधार ही सबसे बड़ी वजह है। ग्रामीण सड़कों में सुधार, बिजली, फोन और ऋण सुविधाएं आदि ने इसमें सहायता की। इससे जागरूकता बढ़ी और उत्पादन की बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हुई। कुछ वर्ष पहले अपने गृह स्थान, बोकारो (झारखंड) में मैंने देखा कि अंडे अलग-अलग ट्रे में रखे थे और उनकी कीमत भी अलग थी। दुकानदार ने बताया कि एक अंडा झारखंड का और दूसरा तमिलनाडु का है। वर्षों से मैं यही जान रहा था कि अंडे तमिलनाडु से आते हैं लेकिन अब झारखंड में भी अंडों का व्यावसायिक उत्पादन आरंभ हो गया है। हमारा यह भी मानना है कि कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में पालतू पशुओं की तादाद बढ़ने का संबंध उत्पादन की गिरती औसत लागत से भी है। इससे संकेत मिलता है कि इन उत्पादों में मंहगाई अपेक्षाकृत कम बनी रहेगी।

कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जिनमें हमने सुधार की अपेक्षा की थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भैंस की तादाद में बदलाव नहीं आया जबकि हमें आशा थी कि इसमें इजाफा होगा। जैसा कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने कहा, भैंसे के मांस का निर्यात 2011-12 से 2016-17 के बीच 34 फीसदी बढ़ा। यानी करीब 1.1 करोड़ भैंसे का इजाफा। पशुपालन विभाग ने कहा कि इस अवधि में जिबह किए गए भैंसे की तादाद में 43 फीसदी का इजाफा हुआ। परंतु एक विसंगति यह है कि पशुगणना में भैंसे की तादाद में किसी बढ़ोतरी का जिक्र नहीं आया। वर्ष 2018 का ब्योरा हमारे पास नहीं है लेकिन 2012 में 10.9 करोड़ भैंस में से केवल 1.6 करोड़ ही भैंसे थे। इनमें भी 1.1 करोड़ की उम्र दो वर्ष से भी कम थी यानी उनके मांस का पूरा इस्तेमाल संभव नहीं था। हम यह समझ नहीं पाए कि कटने के लिए सालाना तकरीबन एक करोड़ भैंसे कहां से आए?

आय में सुधार के साथ खानपान में भी बदलाव आया है। लोग अब पहले से अधिक दूध, मांस और अंडे खरीद और खा सकते हैं। इसका सीधा असर मांग पर पड़ता है। ये प्रारंभिक आंकड़े यह सुझाते हैं कि देश में पालतू पशुओं की तादाद बढ़ने और अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों में इस उद्योग का विकास होने से इस मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता निर्मित हो रही है।

भौगोलिक विविधता ने भी स्थानीय आपूर्ति को बीमारियों या मौसम के कारण होने वाली बाधा से बचाव प्रदान किया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पशु उत्पादों की हिस्सेदारी 11 फीसदी है जबकि गत वर्ष के अंत में एकदम निचले स्तर पर गिरने के बाद हाल के महीनों में इन उत्पादों की महंगाई में थोड़ा इजाफा हुआ है लेकिन इसके ऊंचे स्तर पर बने रहने की आशंका नहीं है।

इस दृष्टि से देखें तो बढ़ती घरेलू मांग और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिए हमें उत्पादकता को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा करके ही यह क्षेत्र निर्यात से अधिक से अधिक आय जुटा सकता है।

पारंपरिक और पोषक भोजन से समृद्ध फर्स्ट फूड का संस्करण

जंक फूड नहीं बल्कि अच्छा भोजन ही प्राथमिक भोजन यानी फर्स्ट फूड है। यह वह भोजन है जो प्रकृति और पोषण को आजीविकाओं के साथ जोड़ता है। यह भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, यह हमारी समृद्ध जैव विविधता से प्राप्त होता है और लोगों को रोजगार प्रदान करता है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसे पकाने और खाने से हमें न केवल खुशी, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य भी मिलता है।

सन 2013 में सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वॉयरनमेंट, यानी वह संस्थान जिसके साथ मैं काम करती हूं, ने फर्स्ट फूड (प्राथमिक खाद्य) का पहला संस्करण प्रकाशित किया था। उस वक्त मैंने लिखा था कि भोजन का संबंध संस्कृति और सबसे अधिक जैव विविधता से है। हम अक्सर इस बारे में विचार नहीं करते कि जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता का संबंध जैव जगत की विविधता से है। हमने दलील दी कि हमें पौधों के बारे में जानकारी और उनके गुणों को पहचानते हुए इस बेहतरी के साथ भोजन पकाना चाहिए कि खाद्य पदार्थों की खुशबू बरकरार रहे। अगर हम अपने खाने की थाली में मौजूद जैव विविधता की कीमत समझेंगे तभी तो वनों की जैव विविधता की रक्षा करेंगे।

सन 2017 में फर्स्ट फूड: कल्चर ऑफ टेस्ट का प्रकाशन किया गया। पहली पुस्तक की तरह इस पुस्तक में भी हमने उन खाद्य पदार्थों को बनाने की विधि संकलित की हैं जो हमें जैव विविधता की जानकारी देती हैं। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तब तक यह पता चल चुका था कि दुनिया मोटापे की समस्या से जूझ रही है। यह बात स्पष्ट है कि हम जो भोजन कर रहे हैं वह हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है। इसमें कोई पोषण या अच्छाई नहीं है।

सबसे महत्त्वपूर्ण बात, अब यह स्पष्ट है कि हमारे भोजन में आया यह बदलाव यानी घर में पके पौष्टिक खाने से दूरी बनाने और सदियों पुरानी खाद्य परंपराओं से दूर जाने का यह सिलसिला संयोगवश नहीं है। हम उस पीढ़ी से आते हैं जो प्रसंस्कृत और फैक्टरी निर्मित खाना खाने वाली है, जिन्हें मार्केटिंग के बल पर बढ़ावा दिया गया। इसने हमारी आदत और खाद्य संस्कृति में बदलाव लाया।

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

भोजन के इस नए कारोबार में बदलाव लाने का काम रसोइये कर सकते हैं। वे हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं और समाज को यह बताते हैं कि कौन सा भोजन बेहतर है।

सवाल यह है कि हम खराब भोजन की इस संस्कृति में बदलाव कैसे लाएं? क्या ऐसा करना संभव है? प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग बहुत ताकतवर है। उनके पास लोगों, खासकर युवाओं को अपने साथ जोड़ने की क्षमता है। वे खानपान के रंग, गंध और खुशबू के सहारे लोगों को लुभाते हैं। उन्हें पता है कि हमें कैसे लुभाना है। यह जानते हुए भी कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरा है। सबसे अहम बात यह है कि प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग ने अब हमारी व्यस्त जीवनशैली का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। यह आसान है क्योंकि यह उपलब्ध है और इसे बनाना आसान है। कोई समस्या ही नहीं।

सबसे अहम बात यह है कि खानपान की उनकी दुनिया उनका कारोबार है। यह इसलिए चलता है क्योंकि उन्हें मुनाफा कमाना है। यही वजह है कि कंपनियां भोजन को हम तक पहुंचाने की आपूर्ति श्रृंखला तैयार करती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अच्छे भोजन की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाए? क्या आजीविका का यह कारोबार मुख्य धारा के खाद्य उद्योग का हिस्सा बन सकता है या इसे अपने बचाव के लिए समांतर बाजार की आवश्यकता है? यह कैसे होगा?

यही कारण है कि फर्स्ट फूड के 2019 के संस्करण में हम ऐसी आजीविका की जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं जो फर्स्ट फूड से जुड़ी हो। इसका संबंध कारोबार से है जो अदृश्य और एक तरह से नवजात है। परंतु इसका संबंध एक ऐसे कारोबार से भी है जिसे भरपूर ढंग से विकसित होना चाहिए। हम जानते हैं कि ऐसा संभव है। इथियोपिया का एक मोटा अनाज है टेफ जिसके बहुत छोटे-छोटे बीज होते हैं। यह ग्लूटेन रहित होता है और यही इसका सबसे बड़ा गुण है। इस बीज को कॉफी के बाद दुनिया को इथियोपिया का दूसरा तोहफा माना जाता है। लंदन में टेफ के एक किलो आटे की कीमत करीब 7 पाउंड है यानी करीब 614 रुपये प्रति किलो। इथियोपिया में यह इससे आधे से भी कम कीमत पर मिलता है।

भारत में भी इसके उदाहरण हैं। रागी और ब्राउन टॉप मिलेट अब हमारे खाद्य बाजारों में प्रमुखता से नजर आ रहा है। हम अब इन्हें खा रहे हैं क्योंकि ये उपलब्ध हैं। परंतु अच्छे खाद्य पदार्थ की इस वृद्धि को बढ़ावा देना होगा ताकि यह हमारे जीवन में रच बस जाए। हमने इस खाद्यान्न के कारोबार की संभावनाओं को भी तलाशा। ठीक उसी तरह जैसे चाय उद्योग छोटे किसानों को साथ लेकर रोजेल्ले फ्लावर्स (लाल अंबारी) एकत्रित कर रहा है या फिर जैसे कटहल का कारोबार इस तरह विकसित हुआ कि अब यह साल भर उपलब्ध रहता है। ये बातें बहुत अहम हैं। हो सकता है कि ये आज हमारी बुरे खानपान की आदतों को बदलने के लिहाज से पर्याप्त न हों लेकिन ये हमें भविष्य की राह तो दिखाती हैं।

भोजन के इस नए कारोबार में बदलाव लाने का काम शेफ यानी रसोइये कर सकते हैं। वे हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं और समाज को यह बताते हैं कि कौन सा भोजन बेहतर है। यही कारण है कि ये वे लोग हैं जो भोजन, पोषण, प्रकृति और आजीविका के बीच के इस नए संबंध को आकार दे सकते हैं। यही कारण है कि फर्स्ट फूड के इस विशेष संस्करण में हमने पाक कला में महारत रखने वाले स्त्री-पुरुषों के ज्ञान का इस्तेमाल किया है। भोजन का यह फैशन हमारे लिए अच्छा होगा।

कानाफूसी

समय की बरबादी

पिछले दिनों मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री ओकार सिंह मरकाम अनचाहे ही एक विमान में चार घंटे से भी अधिक समय तक फंसे रहे। यह वाकया भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे पर हुआ। वह दिल्ली से जबलपुर यात्रा पर थे लेकिन खराब मौसम के कारण विमान को भोपाल ही उतारना पड़ा। मंत्री के पास विमान में बैठे रहने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। उन्होंने विमानन कंपनी और विमानतल के अधिकारियों से बार-बार अनुरोध किया कि उन्हें शहर में स्थित उनके बंगले पर जाने दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह इस समय का उपयोग कुछ जरूरी फाइलें निपटाने में करना चाहते हैं और बुलाए जाने पर तत्काल हवाई अड्डे लौट आएंगे। परंतु उनकी एक न सुनी गई। यह सुनने में आया है कि मंत्री ने विमानन सचिव के पास मामले की शिकायत दर्ज की है।

शुभकामनाओं से आजिज

जिन लोगों को व्हाट्स ऐप पर आने वाले अनचाहे बधाई संदेशों, सुप्रभात संदेशों या अन्य फॉरवर्ड किए गए संदेशों से आपत्ति है, वे खुद को इस घटना से जोड़कर देख सकते हैं। इस बार व्हाट्स ऐप का शिकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए हैं। पिछले दिनों श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उन्हें अपने कनिष्ठ न्यायिक अधिकारियों से लगातार शुभकामना संदेश प्राप्त हो रहे थे। इस पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने सभी जिला न्यायाधीशों को एक निर्देश जारी किया। उनसे कहा गया कि वे शुभकामना संदेश भेजने पर तुरंत रोक लगाएं। पंजीयक ने कहा कि इस संबंध में किसी भी तरह की चूक को गंभीरता से लिया जाएगा।

आपका पक्ष

वाहन उद्योग नीति में बदलाव की जरूरत

वाहन उद्योग में मंदी की मार पड़ रही है और इस उद्योग से जुड़े कर्मचारियों की नौकरियां जा रही हैं। वाहन निर्माताओं के संगठन सायम के अनुसार इस साल वाहनों की कुल बिक्री 12.35 प्रतिशत घट कर 60.85 लाख वाहन रही। पिछले साल यह आंकड़ा 69.42 लाख था। बाजार में मंदी की आहट से लोग नए वाहन नहीं खरीद रहे हैं। इससे वाहन उद्योग में मंदी छा गई है। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाहन उद्योग के लिए कई घोषणाएं की हैं। लेकिन उनकी घोषणाएं से इस उद्योग का एकदम उबर पाना मुश्किल ही लग रहा है। वित्त मंत्री ने अपनी घोषणाओं में कहा कि मार्च 2020 तक खरीदे गए बीएस -4 वाहनों को उनके पंजीकरण की पूरी अवधि तक चलाया जा सकेगा। इसका अर्थ है कि बीएस-4 वाहन के पंजीकरण से 15 वर्षों तक चलाया जा सकेगा। देश में

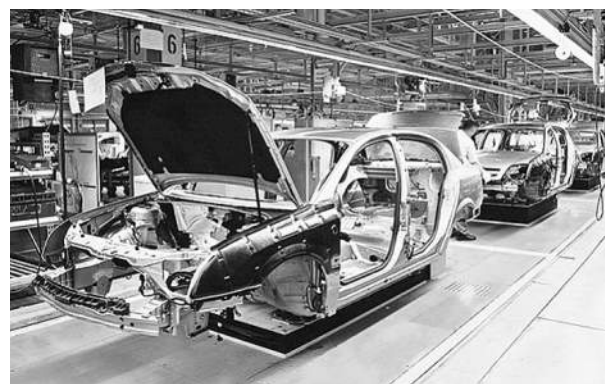

वाहन उद्योग में छा रही मंदी से निपटने के लिए सरकार को नीतियों में बदलाव करना चाहिए

पर्यावरण की चिंता के मद्देनजर बीएस-6 वाहन तथा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए बीएस-4 वाहनों के निर्माण के बजाय सरकार ने बीएस-6 वाहन निर्माण के लिए कहा है। वहीं सरकार की मंशा है कि आने वाले वर्षों में देश में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही चलाए जाएं। इससे तेल आयात पर लगाम लग सकेगी जिससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होने से बच जाएगी। इसके अलावा पर्यावरण का भी बचाव हो सकेगा। सरकार का यह कदम पेरिस जलवायु समझौते के तहत कार्बन उत्सर्जन कम करने का प्रयास भी है। वित्त मंत्री ने कबाड़ नीति लाने की बात भी कही है। आमतौर पर एक वाहन का जीवन 15 वर्ष तय किया गया है। इसके बाद इसके चलाए जाने पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसा माना जाता है कि 15 वर्षों के बाद उक्त वाहन अधिक प्रदूषण छोड़ता है। वित्त मंत्री की घोषणाओं से वाहन उद्योग को आस तो दिखी है लेकिन इसका कितना फायदा होगा यह कहना मुश्किल है। सरकार को वाहन नीति में बदलाव करने की जरूरत है। जो वाहन गैस या बिजली से चलती है उसकी जीवन अवधि बढ़ाने की जरूरत है जो वर्तमान में पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहन की 15 वर्ष तय की गई है। इसी प्रकार अन्य नीतियों में बदलाव की भी जरूरत है।

बृजमोहन कुमार, नई दिल्ली

तकनीक से आपदा पर लगेगी रोक

बाढ़ को रोकने के लिए प्रतिरोधात्मक उपाय न अपनाकर बाढ़ आने पर बचाव व राहत कार्यों पर अधिक जोर दिया गया है। इसके उदाहरण बिहार, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र में आई बाढ़ हैं। परंतु इन पर नियंत्रण नहीं किया जा सका है। ऐसे क्षेत्रों जहां नदियों की निचली धाराओं में बाढ़ आती है, उन पर बड़े-बड़े बांध बनाकर जलाशयों में वर्षा के पानी को रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मॉनसून के दौरान गांव व उसकी सहायक नदियों के पैटर्न को समझने के लिए समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। भूमि सर्वेक्षण की अपेक्षा सरकार को उपग्रह चित्रों पर आधारित नक्शों व भौगालिक सूचना तंत्र जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। बिहार की कोशी नदी जिस प्रकार हर बार अपने बहाव में परिवर्तन करती है, ऐसी नदियों के व्यवहार को समझकर सुरक्षात्मक प्रयास करने चाहिए।

पंकज कुमार निराला, छत्तीसगढ़

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।